विकास का एक नुस्खा

लेखक - अमर्त्य लाहिड़ी (अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, रॉयल बैंक के अनुसंधान प्रोफेसर और जोहल अध्यक्ष, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, कनाडा)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

1 जून, 2019

"भारत को अपने अतीत से सीखना चाहिए और महत्त्वपूर्ण सुधारों को गति देना चाहिए।"

आज भारत जिस विकास से संबंधित चुनौती का सामना कर रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ आंकड़ों पर ध्यान देना उपयोगी साबित होगा। भारत का वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर है जबकि इसका प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,000 डॉलर है। 1.1 प्रतिशत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि और 6.6 प्रतिशत सकल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के साथ, भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान में 5.5 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रहा है। इन विकास दर पर, भारत का प्रति व्यक्ति जीडीपी 2060 में लगभग 19,000 डॉलर होगा।

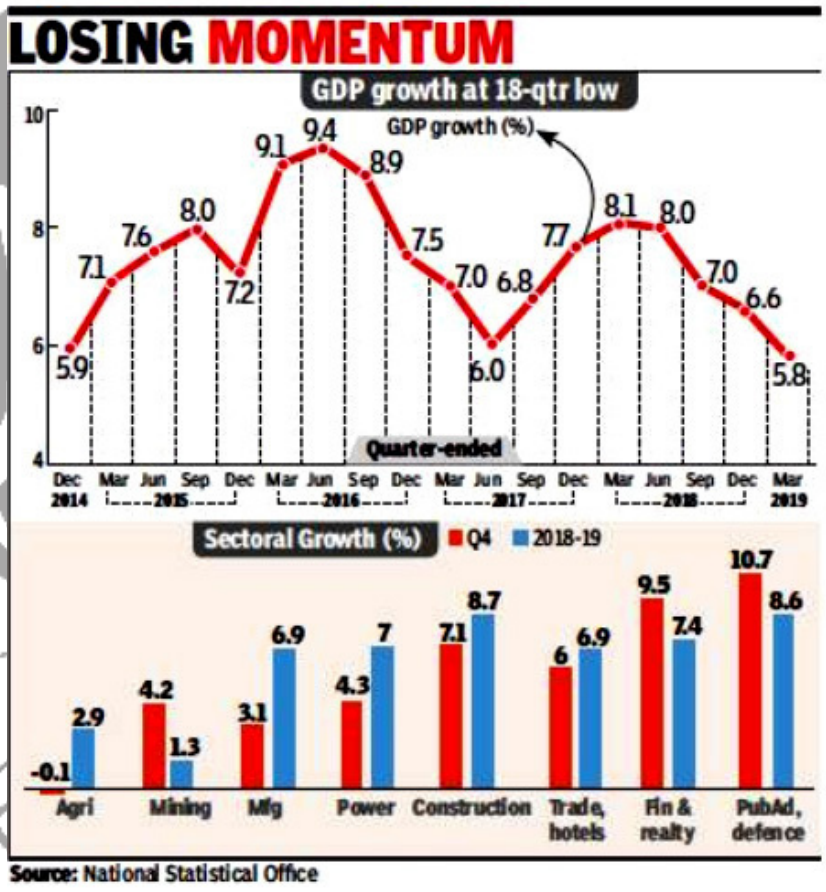

Source: National Statistical Office

इस परिदृश्य को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, ग्रीस का प्रति व्यक्ति जीडीपी आज लगभग 20,000 डॉलर है। भले ही भारत अगले 41 वर्षों के लिए 7 प्रतिशत की औसत से विकास दर बनाए रखने का प्रबंधन करे, लेकिन फिर भी भारत का प्रति व्यक्ति जीडीपी ग्रीस के वर्तमान प्रति व्यक्ति जीडीपी से बमुश्किल ऊपर होगा। और ग्रीस वास्तव में एक विकास रोल मॉडल नहीं है।

इन परिदृश्यों के आस-पास अनिश्चितताएं भी बहुत बड़ी हैं। यदि औसत कुल विकास दर गिरकर 5.6 प्रतिशत हो जाती है, तो 2060 में भारत का प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 12,000 डॉलर होगा, जो आज चीन में प्रति व्यक्ति जीडीपी से थोड़ा ही अधिक है। यह भारत में निहित जोखिम है जो अपने वर्तमान विकास पथ और अपनी विकास चुनौती के पैमाने से थोड़ा फिसल रहा है।

भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर विकास एक चुनौती बन गया है। दुनिया के सबसे अमीर 5 फीसदी देशों में से प्रति व्यक्ति जीडीपी सबसे गरीब 5 फीसदी लोगों की जीडीपी से 50 गुना ज्यादा है। इसलिए हमे जानना होगा कि देशों में ऐसी बड़ी असमानताएं क्या दर्शाती हैं?

आउटपुट विभिन्न कौशल प्रकारों, भूमि, पूंजी, ऊर्जा और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के श्रम के संयोजन से उत्पन्न होता है। इन निविष्टियों के संयोजन के लिए उद्यमशीलता और प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, फर्म के स्तर पर, जो प्रबंधक व्यक्तिगत श्रमिकों के कार्यों के कौशल से मेल खाते हैं, वे उच्च राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम हैं। यह देश के स्तर पर भी

लागू होता है। यह अमोघ एक्स-फैक्टर है जिसे आमतौर पर उत्पादकता के रूप में जाना जाता है।

कई शोधकर्ताओं ने पाया है कि मापित इनपुट देशों में उत्पादन में प्रति व्यक्ति अंतर के आधे हिस्से का कारण हैं। शेष उत्पादन अंतर पूरे देशों में उत्पादकता स्तरों में अंतर के कारण है। किसी कारण से, समान माप इनपुट गरीब देशों के सापेक्ष अमीर देशों में बहुत अधिक उत्पादन करते हैं।

अब सवाल उठता है कि वह कौन सा गुप्त रहस्य है जिसका उपयोग अमीर देश करते हैं जो उन्हें इतना उत्पादक बनाता है? पहला, स्पष्ट रूप से देश में नीति का माहौल है। अर्थव्यवस्थाएं जो पूंजी और श्रम को आसानी से अपने सबसे अधिक उत्पादक उपयोग की ओर फर्मों, क्षेत्रों और देशों में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं वे सबसे अधिक उत्पादक बनती है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएँ जहाँ ऐसी गतिशीलता प्रतिबंधित है, वहाँ श्रम और पूँजी का अधिक दुरुपयोग होता है।

देशों में उत्पादकता में अंतर का एक दूसरा कारण संस्थानों की गुणवत्ता है। अनुबंधों के प्रकार जो व्यक्तियों और व्यवसायों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं वे कानून का शासन, कानूनों की प्रकृति, अनुबंधों और संपत्ति के अधिकारों का प्रवर्तन, सार्वजनिक डेटा और सूचना की विश्वसनीयता, कानून प्रवर्तन और सार्वजनिक सूचना के प्रसार की निगरानी करने वाली एजेंसियों की स्वतंत्रता पर निर्भर करते हैं।

यह भारत पर कैसे लागू होता है? स्पष्ट रूप से, इनपुट की आपूर्ति में कई बाधाएं हैं। कारखानों के निर्माण के लिए व्यवसायों की और नवीनतम तकनीकों के लिए विदेशी भागीदारों की आवश्यकता होती है। श्रम को अवशोषित करने के लिए कारखानों की आवश्यकता होती है जो भारत के पास है। इस श्रम का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में कृषि में अत्यंत संकटपूर्ण परिस्थितियों में फंसा हुआ है क्योंकि अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं हो रही हैं। इसके अलावा, वर्तमान श्रम कानून फर्मों के लिए बड़े पैमाने पर काम पर रखने को महंगा बनाते हैं। इन्हें संबोधित करने के लिए भारत की मौजूदा भूमि अधिग्रहण और श्रम नीतियों में सुधार की आवश्यकता है।

व्यवसायों को भी पूंजी की आवश्यकता होती है जो वे वित्तीय बाजारों से प्राप्त करते हैं। इसके लिए एक स्वस्थ क्रेडिट संस्कृति की आवश्यकता होती है जिसमें ऋण चुकाए जाते हैं, दिवालियापन को त्वरित और व्यवस्थित तरीके से निपटाया जाता है और बैंक सबसे अधिक उत्पादक उधारकर्ता को ऋण देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हमारा बैंकिंग क्षेत्र ज्यादातर राज्य द्वारा नियंत्रित है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने, सांविधिक चलनिधि अनुपात और निर्देशित ऋण देने के लिए अनौपचारिक दबावों के कारण बैंकों को ऋण देने में असंख्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

बार-बार लोन माफ करने से बैंकों के लिए लोन वसूलना मुश्किल हो गया है। दिवाला और दिवालियापन संहिता की शुरूआत एक उत्कृष्ट पहल रही है, लेकिन इसके तहत संकल्प अभी भी धीमी गति से चल रहे हैं। यह सब निजी व्यवसायों के लिए निधियों की लागत को बढ़ाता है। बैंक के निजीकरण सहित वित्तीय क्षेत्र में सुधार की स्पष्ट रूप से आवश्यकता है।

आम तौर पर, निजी व्यवसायों, स्थानीय और विश्व स्तर पर, को यह महसूस करने की आवश्यकता है कि भारत व्यापार के अनुकूल है, इसकी औद्योगिक और व्यापार नीतियां अचानक उलट-पलट के अधीन नहीं हैं, प्रवर्तन एजेंसियां स्वतंत्र हैं, सार्वजनिक डेटा विश्वसनीय है और देश अपने बाजार के बुनियादी ढांचे की देखरेख में क्षेत्रीय विशेषज्ञों को महत्व देता है। यह भारत के संस्थागत ढांचे में विश्वास पैदा करेगा जिससे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से अधिक से अधिक निवेश और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा सके।

जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रदर्शन में अपेक्षाकृत छोटे परिवर्तन निरंतर अवधि में संभावित परिणामों में व्यापक विचलन उत्पन्न कर सकते हैं। चालीस साल पूरी पीढ़ी का कामकाजी जीवन होता है। 1950 से 1990 की अवधि में पहले से ही एक पीढ़ी मुश्किल से आय में वृद्धि का अनुभव कर रही थी। भारत ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकता। विकास एक लंबा खेल है। भारत को अब कार्यवाही करने और नए पाठ्यक्रम पर बने रहने की जरूरत है।

भारत का जीडीपी- 2019

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जीडीपी और रोजगार से जुड़े तमाम आंकड़े जारी कर दिए हैं।
- जिसके अनुसार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की संवृद्धि दर पिछले पांच साल के निचले स्तर पर आ गई है।
- दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी के रूप में बढ़ने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था अपने पांच साल के निचले स्तर पर आ गई है।
- लेबर सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 में देश में बेरोजगारी दर भी 6.1% पर रही है।
- निवेश की रफ्तार धीमी बनी हुई है। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉरमेशन की दर घटकर 30.7 फीसद पर आ गई है जो पिछले कई वर्षों में काफी कम है।

आंकड़ों के अनुसार

- आंकड़ों के अनुसार जनवरी-मार्च की तिमाही में जीडीपी की दर घटकर 5.8 फीसदी हो गई है। इसकी वजह पिछले 9 महीने में देश में कृषि, उद्योग और मैनुफैक्चरिंग जैसे अहम सेक्टरों में मंदी रहना है।
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने यह भी बताया कि 2018-19 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रही, जो पिछले वित्त वर्ष में 7.2% से कम थी, यह पिछले पांच साल में सबसे कम है। ।
- 2013-14 में विकास दर 6.4% दर्ज की गई थी।
- विकास दर पूरे साल की जीडीपी का औसत होता है। यानी कि जीडीपी हर तीन महीने में जारी होती है और विकास दर का आंकड़ा पूरे साल का होता है।
- दूसरी ओर, चीन ने जनवरी-मार्च, 2019 की तिमाही में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेज प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देश से हट गया।
- नियंत्रक महालेखाकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार के राजस्व में 1.6 ट्रिलियन से अधिक की कमी देखी गई है।

रोजगार के संबंध में

- श्रम मंत्रालय के अनुसार, सभी नियोजित शहरी युवाओं में से 7.8 प्रतिशत बेरोजगार हैं, जबकि ग्रामीण का प्रतिशत 5.3 प्रतिशत था।
- अखिल भारतीय आधार पर पुरुषों में बेरोजगारी 6.2 प्रतिशत थी, जबकि महिलाओं के मामले में यह 5.7 प्रतिशत थी।
- 2017-18 में, मासिक प्रति व्यक्ति आय 9,580रु थी।
- प्रति व्यक्ति आय किसी देश की समृद्धि का एक कच्चा संकेतक है।
- मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान देश की प्रति व्यक्ति आय 10% बढ़कर ˙ 10,534रु प्रति माह होने का अनुमान है।
- 2017-18 के दौरान 169.10 लाख करोड़ की तुलना में मौजूदा कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय (GNI) 2018-19 के दौरान 188.17 लाख करोड़ अनुमानित है, अर्थात 11.3% की वृद्धि।

क्या था पिछला आंकड़ा?

- 2017-18 में जनवरी-मार्च में जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.1 फीसदी रही थी। वहीं 2017-18 में देश की विकास दर 7.2 फीसदी थी।
- सरकार ने अनुमान लगाया था कि इस मार्च की तिमाही में जीडीपी दर 6.5 फीसदी और वित्तवर्ष 2019 में विकास दर 7.1 फीसदी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
- जीडीपी की दर घटकर 5.8 फीसदी रह गई और विकास दर घटकर 6.8 फीसदी रह गई है।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

- जीडीपी एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम सामानों और सेवाओं के बाजार मूल्य की मौद्रिक माप है। सामान्यत: जीडीपी दो प्रकार की होती है:
- नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) और वास्तविक जीडीपी (Real GDP)
- वास्तविक जीडीपी को मुद्रास्फीति के लिये समायोजित किया जाता है, जबकि नाममात्र जीडीपी को मुद्रास्फीति के लिये समायोजित नहीं किया जाता है। इसलिये नाममात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी से हमेशा अधिक दिखाई देती है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी जनवरी-मार्च की तिमाही में घटकर 6.84 फीसदी हो गई है।
2. जीडीपी प्रत्येक दो वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य की मौद्रिक माप है।
3. 2018-19 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रही।
4. विकास दर पूरे साल की जीडीपी का अनुपात होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 1 और 3
(d) केवल 3

Q. Consider the following statements:

1. According to the statistics of the Central Statistical Office, India's GDP has decreased to 6.84% in the January-March quarter.
2. GDP is the monetary measure of the market value of all the final goods and services produced during each two years.
3. GDP growth rate of 6.8% during 2018-19
4. Growth rate is the ratio of GDP to the whole year.

Which of the statement above is/are true?

(a) only 1
(b) 1 and 2
(c) 1 and 3
(d) Only 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख विभिन्न चुनौतियों का उल्लेख करते हुए बताएं कि सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? (250 शब्द)

Q. Discussing the various challenges facing the Indian economy and what steps should be taken by the government to deal with these challenges? (250Words)

नोट : 31 मई को <u>भारतीय अर्थव्यवस्था</u> से संबंधित आलेख में दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।
नोट : 31 मई को <u>पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी</u> से संबंधित आलेख में दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

Comm